



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 719]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 6, 2009/वैशाख 16, 1931

No. 719]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 2009/VAISAKHA 16, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2009

सं. 104 (आर ई-2009)/2004—2009

का.आ. 1177(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2004-2009 के पैराग्राफ 1.3 तथा पैरा 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 3 (2) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. 93 (आर ई-2007)/2004-09 दिनांक 1 अप्रैल, 2008 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है :—

2. निम्नलिखित को अधिसूचना सं. 93 (आर ई-2007)/2004-2009 दिनांक, 1 अप्रैल, 2008 के पैरा 2.1 के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

"2.1.9 गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध निम्नलिखित देशों को चावल के निर्यात पर लागू नहीं होगा :—

क्रम सं.	देश	मात्रा मी. टन में	पीएसयू का नाम जिसके माध्यम से निर्यात किया जाना है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बुरुकिना फासो	24,200	एमएमटीसी
2.	कैमरून	21,700	
3.	कोट डी आइवरी	1,44,900	
4.	मिस्र	48,300	

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	द गैम्बिया	36,250	एमएमटीसी
6.	माली	24,200	
7.	सोमालिया	24,200	
8.	ट्यूनीशिया	5,550	
9.	जंजीबार	12,100	
10.	बेनिन	24,200	एसटीसी
11.	घाना	68,800	
12.	गुनि बिसाऊ	24,200	
13.	लाइबेरिया	96,600	
14.	मोजाम्बिक	24,200	
15.	टोगो	72,400	पीईसी
16.	जाम्बिया	24,200	
17.	नाइजीरिया	1,17,100	
18.	सेनेगल	1,41,300	
19.	मारीशस	15,000	
20.	सिएरा लियोन	38,500	पीईसी
21.	जिबूटी	12,100	
कुल		10,00,000	

उपरोक्त निर्यात निम्नलिखित शर्तों के मद्दे होगा :—

- उपरोक्त मात्रा के एमएस 2008-09 के दौरान पीएसयू के द्वारा निर्यात की जाएगी;
- उपरोक्त पीएसयू ऐसी मिलों से चावल प्राप्त करेंगे जिनके स्टॉक में चावल/धान आधिक्य में होगा;
- निर्यात किए जाने वाले चावल में कम से कम 25: दूटा चावल होना चाहिए;
- पीएसयू यह सुनिश्चित करेगा कि इस निर्यात के लिए उनका बाजार में प्रवेश चावल की समग्र मूल्य स्थिति को प्रभावित न करे; और

- v. पीएसयू निर्यात किए जाने वाले चावल को एक से अधिक राज्यों से प्राप्त करेगा।
3. अधिसूचना सं. 93 (आर ई-2007)/2004-09 दिनांक 1 अप्रैल, 2008 के अन्य सभी प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे और लागू रहेंगे।
4. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/91/180/846/ए एम 08/-निर्यात सेल]  
आर. एस. गुजराल, विदेश व्यापार महानिदेशक  
एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
(Department of Commerce)  
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th May, 2009

No. 104 (RE-2009)/2004-2009

S.O. 1177(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 read with Section 3(2) of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) and also read with Para 1.3 and Para 2.1 of the Foreign Trade Policy, 2004-2009, the Central Government hereby makes, with immediate effect, following amendments to Notification No. 93 (RE-2007)/2004-2009 dated 1st April, 2008 as amended from time to time.

2. Following shall be added at the end of Para 2.1 of the Notification No. 93 (RE-2007)/2004-2009 dated 1st April, 2008 :—

“2.1.9 Ban on export of non-basmati rice shall not be applicable to export of rice to the following countries :—

Sl. No.	Country	Quantity in MTs.	Name of PUS through which export to be made
1	2	3	4
1.	Burkina Faso	24,200	MMTC
2.	Cameroon	21,700	
3.	Cote D'Ivoire	1,44,900	
4.	Egypt	48,300	
5.	The Gambia	36,250	

1	2	3	4
6.	Mali	24,200	MMTC
7.	Somalia	24,200	
8.	Tunisia	5,550	
9.	Zanzibar	12,100	
10.	Benin	24,200	STC
11.	Ghana	68,800	
12.	Guinea Bissau	24,200	
13.	Liberia	96,600	
14.	Mozambique	24,200	
15.	Togo	72,400	
16.	Zambia	24,200	PEC
17.	Nigeria	1,17,100	
18.	Senegal	1,41,300	
19.	Mauritius	15,000	
20.	Sierra Leone	38,500	
21.	Djibouti	12,100	
<b>Total</b>		<b>10,00,000</b>	

The above export shall be subject to the following conditions :—

- The above quantity shall be exported by PSUs during KMS 2008-09;
- Above PSUs shall procure rice from such rice mills which have surplus rice/paddy in their stock;
- The rice to be exported shall be with a minimum of 25% of Broken;
- The PSUs shall ensure that their entry into market for this export does not affect the overall price situation of rice; and
- The PSUs shall source the rice to be exported from more than one State.”

3. All other provisions of the Notification No. 93 (RE-2007)/2004-09 dated 1st April, 2008 shall remain unchanged, and shall continue to apply.

4. This issues in public interest.

[F. No. 01/91/180/846/AM 08/Export Cell]

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade  
and ex-officio Addl. Secy.